संभल जाओ दिल्ली...किसानों को बार-बार मत बुलाओ... वरना तुम्हारे तख्त उछाले जाएंगे...मुखौटे उतारे जाएंगे

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नई दिल्ली: दिल्ली के दरवाजे पर किसानों ने अक्टूबर में दस्तक दी थी और 29-30 नवंबर को फिर से दस्तक दी। इससे पहले तमिलनाडु के किसानों, महाराष्ट्र, पंजाब-हरियाणा के किसानों के दिल्ली मार्च को भी जोड़ लिया जाए तो तस्वीर साफ हो जाती है कि आखिर दिल्ली के दरवाजे पर देश का किसान बार-बार दस्तक दे रहा है। लेकिन किसान जंतर-मंतर के जिस गोल चक्कर पर आकर हर बार आकर शांति से लौट जाते हैं वह शांति बहुत दिनों तक बनी नहीं रहने वाली है। देश का किसान इतना निराश है कि उसे जो भी गोलबंद करके संघर्ष छेड़ने की ताकत रखता है, उसके साथ वे गोलबंद होने को तैयार हैं। नहीं तो क्या वजह है कि 29 नवंबर को रामलीला मैदान में और 30 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर सीपीएम-सीपीआई के लाल झंडे के अलावा हरियाणा से योगेंद्र यादव के नेतृत्व में आए किसान पीला झंडा लहरा रहे थे तो यूपी से भारतीय किसान यूनियन का झंडा लेकर वहां के किसान पहुंचे थे। सबका मकसद एक ही था कि दिल्ली की संसद में बैठी नरेंद्र मोदी की गूंगी बहरी सरकार किसानों की बात सुने। इस किसान मार्च की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि किसानों के मंच पर सारा विपक्ष एकजुट हो गया। हर बड़ी और महत्वूर्ण पार्टी का नेता इस मंच पर पहुंचा।

मुंबई के बाद दिल्ली में किसान मार्च का शानदार जुटान, और शहरी आम जनता की उसके साथ हमदर्दी, एक बार फिर बता रहा है कि सवाल जनजीवन से जुड़े हों तो मेहनतकश जनता ने संघर्ष हेतु जुटने में कभी चूक नहीं की। इसलिए आंदोलनों की कमजोरियों के लिए आम मेहनतकश जनता को दोष देना कतई गलत है, जैसा अक्सर हताशा में किया जाता है। कमजोरी तो जनता के सवालों पर संयुक्त संघर्षों के बजाय चुनावी राजनीति को ही मुख्य मकसद बना बैठे वाम नेतृत्व में ही है।

लेकिन यह भी कहना जरूरी है कि समस्या के समाधान का जो रास्ता बताया जा रहा है - कर्ज माफी, डेढ़ गुनाएमएसपी - उससे 85 प्रतिशत छोटी जोत वाले किसानों तथा ग्रामीण जनता के आधे से अधिक श्रमिकों के जीवन में सुधार होने वाला नहीं। इन दोनों का फायदा सिर्फ 5-6 प्रतिशत बढ़े किसानों

को ही होता है जो श्रमिकों और यंत्रों के साथ आज भी लाभदायक खेती कर रहे हैं। न ही इन सीमांत किसानों को इन छोटी-छोटी जोतों में ही बांधे रखने और उसमें ही लाभ प्राप्त कर लेने का छद्म भ्रम दिखाने से ही कुछ हासिल होने वाला है। एमएसपी को डेढ़ क्या दो गुना भी कर दीजिये, ये एकड़-दो एकड़ के जमीन के टुकड़े किसान को कभी अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते। ये टुकड़े आगे और भी छोटे ही होते जाएंगे। कृषि से जुड़ी बड़ी आबादी के लिए इससे बाहर रोजगार का इंतजाम करना ही होगा जो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था में नामुमकिन हो चुका है।

अगर सारे किसान घाटे में हैं तो वे कौन हैं जो एक हेक्टेयर कृषि भूमि को भाड़े पर लेने के लिए सालाना 50 हजार से डेढ़ लाख तक दे रहे हैं? इनके पास ये भाड़ा देने का पैसा कहाँ से आता है अगर सारी खेती ही अलाभकारी है? क्या इन 'फार्मर किसानों' और छोटे-छोटे जमीन के टुकड़ों पर कंगाली और कर्ज में डूबे 85 प्रतिशत छोटे-सीमांत किसानों के हित समान हैं, या परस्पर विपरीत? क्या दोनों 'किसान' तबकों की खेती एक साथ लाभकारी बनाई जा सकती है? फिर खेती से जुड़ी आबादी में 54 प्रतिशत खेत मजदूर भी हैं। क्या ये फार्मर इनका शोषण नहीं करते, इनके श्रम से उत्पन्न अधिशेष से ही अमीर नहीं बनते? इस श्रमिक आबादी के हितों की बात न करने वाले कैसी मजदूर वर्ग राजनीति करते हैं? जिन लाखों किसान आत्महत्याओं की चर्चा की जाती है क्या वे पहले लाभकारी फार्मरों द्वारा की जाती हैं या कर्ज-कंगाली में डूबे छोटे किसानों व खेत मजदूरों द्वारा? क्या दोनों तबकों के किसानों व खेतिहर मजदूरों के हित एक साथ पूरे किए जा सकते हैं? इन सवालों पर गंभीर चर्चा के बिना 'किसानों' की तबाही के नाम पर बहाये गए आँसू और हमदर्दी घड़ियाली ही है।

कुछ दिन पहले पी साईनाथ ने बताया कि 'पिछले 20 सालों में हर दिन दो हज़ार किसान खेती छोड़ रहे हैं. ऐसे किसानों की संख्या लगातार घट रही है जिनकी अपनी खेतीहर ज़मीन हुआ करती थी और ऐसे किसानों की संख्या बढ़ रही है जो किराये पर ज़मीन लेकर खेती कर रहे हैं। इन किरायेदार किसानों में 80 प्रतिशत क़र्ज़ में डूबे हुए हैं। किसानों को कृषि ऋण बांटने की बात की जाती है लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) भी नकद मुंबई में बांट रहा है जहां खेती-किसानी है ही नहीं।

पी साईनाथ ने ये भी खुलासा किया कि मोदी सरकार की फसल बीमा योजना राफेल से बड़ा घोटाला है 'रिलायंस ने एक जिले में 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया और उसे शुद्ध लाभ 143 करोड़ रुपये हुआ, जबकि उसका निवेश एक भी रुपया नहीं था' लेकिन उसके बावजूद बीमा करवाने को किसानों को मजबूर किया गया।

दलाल मीडिया ने किसान मार्च पर तवज्जो नहीं दी

दिल्ली के दलाल मीडिया ने किसानों के इस मार्च को तवज्जो नहीं दी। अभी चंद दिन पहले अयोध्या और मंदिर लेकर जिस तरह चीख-चीख कर उस मुद्दे को हवा दी गई, किसी चैनल का एंकर किसानों के लिए चिल्लाता नहीं दिखा। तमाम चैनलों में अपनी रूटीन खबरों में किसान मार्च के विडियो चलाए लेकिन जिन घटिया मुद्दों पर वे लोग प्राइम टाइम में बहस चलाते हैं, उनके प्राइम टाइम से किसानों का मुद्दा गायब था। कुछ चैनलों के न्यूज रूम में इस बात पर चर्चा हुई कि इस किसान मार्च में बोलेरो, स्कॉर्पियो जैसी एसयूवी लेकर कौन किसान आए हैं। इन चैनलों के पत्रकारों ने एक बार मौके पर जाकर उन एसयूवी वालों से नहीं पूछा कि भैया, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किसानों से आपका क्या संबंध है, तब जरूर चैनल एंकरों को असलियत मालूम हो जाती। महात्मा गांधी ने किसानों को 'भारत की आत्मा' कहा था, लेकिन इन मीडिया हाउसेज को 'भारत की आत्मा' की दुख तकलीफ से कोई मतलब नही है उन्हें तो देश को सांप्रदायिक वैमनस्य की आग में झोंकना ज्यादा मुफीद दिखता है क्योंकि इसी से सत्ताधारी दल के हितसाधन की पूर्ति होती है।

कैसे लुटते हैं किसान

बहुत सारे किसान दुधारू पशु पाल कर भी गुजारा कर रहे हैं। हिमाचल के एक किसान ने जो बताया वह आंख खोलने वाला है जो बताता है कि किसान कैसे लुट रहा है। उस किसान ने बताया कि मेरे माता पिता उना जिले के पनगोडा गाँव में रहते हैं। हम 1981 से गायें पाल रहे हैं। 2012 तक राज्य दुग्ध सहकारिता की गाड़ियाँ आती थीं और छोटे किसानों से दूध ले जाती थीं। जबकि दाम बहुत कम मिलता रहा। 18 रुपये प्रति लीटर। कुछ समय बाद सहकारिता की गाड़ी आनी बंद हो गई। 2016 में पंजाब की वेरका कंपनी ने दूध लेना शुरू कर दिया। आज दाम 23 रुपये प्रति लीटर है। यह दाम शुद्ध दूध का है। हर हफ्ते कंपनी हमारे दूध में वसा की मात्रा की जाँच होती है। वसा की मात्रा बढ़ाने के लिए गाय को विशेष आहार देना पड़ता है जिस पर हर महीने 4000 अलग से ख़र्च हो जाता है। इसके कारण दूध की कीमत 24 रुपये प्रति लीटर मिल जाती है क्योंकि वसा की मात्रा अधिक होती है। चारा, घास कुतरना, मज़दूरी, बिजली का भी ख़र्चा होता है। सूखा चारा सौ रुपये कुंतल आता है। साल में पचास हज़ार लग जाता है हर महीने पंद्रह हज़ार की लागत आती है। अगर हम पाँच लीटर दूध 23 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचते हैं तो तीस दिन में हमारी कमाई होती है 15,600 रुपये होती है। मैं शिमला में रहता हूँ जहाँ 24 रुपये का आधा लीटर दूध ख़रीदता हूँ। वो भी डबल टोन दूध। जबकि अपने घर में 24 रुपये लीटर से कम पर दूध बेचता हूँ। यह हमारे साथ मज़ाक नहीं तो और क्या है।

जब मैंने उनसे पूछा कि छह सौ रुपये के लाभ के लिए कोई इतनी मेहनत क्यों करेगा? तो ये जवाब आया है। कभी हिसाब ही नहीं किया। और शायद फ़ायदा होता भी ना हो। खेती के साथ पशु पालन होता ही है। यह कहानी सभी छोटे ज़मींदारों की है। एक गाँव में रहने वाला ही समझेगा नहीं तो यह बिजनेस लगेगा।

किसान मुक्ति यात्रा- सरकार के दरवाजे पर किसान की दस्तक

दिल्ली से अजातशत्रु की विशेष रिपोर्ट

किसानों के लगभग 200 संगठनों ने आज 29 नवम्बर 2018 को सरकार के दरवाजे खटखटाने की तरफ़ कूच किया। इन सभी संगठनों ने लगभग तीन महीने पहले एक किसान संघर्ष समन्वय समिति बनाई थी और उसके तले संयुक्त रूप से किसानों की मांगों के लिये लड़ने का एलान किया था। उसमें सबसे मुख्य मांग यह है कि किसानों की समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करने के लिये संसद का तीन हफ़्ते का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाय। इसी कड़ी में आज देश भर से किसानों ने दिल्ली की तरफ़ कूच किया।

देश भर से आये किसान जत्थों ने राजधानी में चार स्थान से रामलीला मैदान की तरफ़ कूच किया। मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के जत्थों ने निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन उतरकर वहां से सुबह मार्च शुरू किया। इसमें मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु उड़िसा, महाराष्ट्र व हरियाणा के किसान थे। जत्थे में प्रोफ़ेसर साईनाथ सुनीलम, बादल सरोज, मेघा पाटेकर व अन्य नेता भी शामिल थे।

दूसरा किसान जत्था पंजाब, हिमाचल, हरियाणा व यू.पी. का मजनूं का टीला पर इकट्ठा हुआ जहां से उसने रामलीला मैदान की तरफ़ कूच किया। इसी तरह एक जत्था विजयवासन गांव से तो चौथा जत्था पूर्वी दिल्ली से पैदल यात्रा करता हुआ रामलीला मैदान पहुंचा। शाम होने तक अनुमान है कि

इन चारों जत्थों में शामिल लगभग 25 हजार किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच चुके थे। इसके अलावा लाखों किसान देश के विभिन्न प्रांतों से कल तक इस मार्च में शामिल होने के लिये पहुंच जायेंगे। कल यानी 30 नवम्बर 2018 को लाखों किसानों का ये समूह संसद पर दस्तक देंगे और मांग करेंगे कि संसद का तीन हफ़्ते का एक विशेष सत्र सिर्फ़ किसानों समस्यायें सुलझाने के लिये बुलाया जाये। कल ही इस बारे में लाखों हस्ताक्षरों से युक्त एक ज्ञापन भी राष्ट्रपति को सौंपा जायेगा।

इस किसान आंदोलन की मुख्य रूप से तीन मांगे हैं। किसानों के सभी कर्जे माफ़ करो, फ़सलों के लाभकारी मूल्य दो और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। वैसे तो डॉ. स्वामीनाथन की रिपोर्ट ही इतनी विस्तृत और तथ्यपूर्ण है वह किसानों की लगभग सभी समस्याओं का समाधान कर देती है लेकिन दुख की बात ये है कि सन् 2006 से सरकार के पास जमा इस रिपोर्ट पर न तो कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्यवाही की और ना ही मौजूदा मोदी सरकार ने। यद्यपि दोनों ने ही इस रिपोर्ट को लागू करने का वादा चुनावों के वक्त किया था। डॉ. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ़ किसानों ही नहीं बल्कि देश की सारी गरीब आबादी की समस्याओं, उनके कारणों और निदान के उपायें की विस्तृत चर्चा की है।

आज शाम को रामलीला मैदान में कलाकरों द्वारा 'एक शाम किसानों के नाम' का आयोजन किया जायेगा जो गीत संगीत से भरपूर होगी। अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आसपास के इलाके के भी बहुत सारे लोग रामलीला मैदान में इस कार्यक्रम को देखने पहुंचे। इसके अलावा समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने भी न सिर्फ़ किसानों के आंदोलन का समर्थन किया बल्कि उनके सहयोग में आगे आये। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने किसानों का स्वागत किया व कई जगह चाय-पानी का प्रबन्ध किया। मजनूं का टीला व बाला साहब गुरुद्वारों (महारानी बाग) में सभी किसानों के लिये सुबह से ही लंगर (भोजन) की बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई थी। दिल्ली सरकार ने भी किसानों की सुविधा के लिये पानी, एम्बूलेन्स व शौचालय आदि का प्रबन्ध किया हुआ था। केन्द्र सरकार ने भी पुलिस का व्यापक प्रबन्ध किया हुआ था जो किसानों को घेरे चल रही थी। इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहर लाल यूनिवर्सिटी व जामिया के भी छात्रों, शिक्षकों ने किसानों के समर्थन में मार्च में भाग लिया। बहुत सारे डॉक्टर, इन्जीनियर्स, कर्मचारी भी किसानों से हमदर्दी व्यक्त करते हुये मार्च में शामिल हुये, उन्होंने नेशन फॉर फ़ार्मर्स लिखी हुई टी शर्ट पहन रखी थी।

महाराष्ट्र में तो नासिक से मुम्बई के किसानों के लम्बे मार्च से महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार हिल गयी थी लेकिन मोदी जैसे बेशर्म को गरीब किसानों के इस आंदोलन से कोई असर होगा कहना मुश्किल है। हो सकता है उसका कोई मन्त्री इसको भी पाकिस्तानी षडयन्त्र बता दे या कम्युनिस्टों की मोदी सरकार को गिराने की साजिश। पर इतना तय है कि किसानों के लगातार बढ़ते आंदोलन से यह स्पष्ट है कि किसान समझने लगा है कि मोदी सरकार सिर्फ़ झूठ और जुमलों की सरकार है।

किसानों को हेय समझने वाले हैं गांधी प्रतिष्ठानों में

29 तारीख को किसानों का एक जत्था जब राजघाट के पास से गुजर रहा था तो वहां चाय-पानी की व्यवस्था देख कर रूक गया। कुछ किसान पुरुष व महिलायें गांधी संग्राहलय के शौचालयों में भी घुसे तो वहां तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को लगा मानों 'जंगली' लोग उनके सुन्दर-सुसज्जित भवन को उजाड़ने आ गये हों।

ऊपर से आदेश पा कर गार्ड ने किसानों को धमकाना व रोकना शुरू किया तथा शैचालय का दरवाजा बंद कर दिया। 'मज़दूर मोर्चा' के ग्राऊंड रिपोर्टर ने उसे समझाया कि ये लोग भी इन्सान हैं और इन्हीं लोगों के लिये, इन्ही के पैसे से यह सब कुछ बना हुआ है। जब गार्ड की समझ में बात नहीं आई तो रिपोर्टर ने ज़रा कड़क आवाज़ की तो उसने भी और विरोध किया।

गार्ड के बाद जब किसान बाहर मेन गेट पर आये तो उसे भी बंद कर किसानों को बाहर ही रोक दिया गया। तब तक भीतर बैठे अधिकारी का आदेश गार्ड को मिला और गेट खोल दिया गया। किसानों ने तसल्ली से शौचालय का प्रयोग किया।

उक्त घटना है तो बहुत मामूली सी लेकिन यह दिल्ली में बैठे और वह भी गांधी के नाम की रोटी खाने वाले लोगों की मानसिकता को दर्शाने के लिये पर्याप्त है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06